	IOC	BPCL	HPCL	
Yemenia Yemen Airways	52.46			52.46
Thai Airways	275.00			275.00
Air France	1552.00			1552.00
Scandinavian Airlines System	199.00			199.00
United Airlines	489.00			489.00
Turkemenistan Airlines	12.00			12.00
Austrian Airlines	16.00			16.00
North West Airlines	54.00	160.89		214.89
Malaysian Airlines	88.20			88.20
British Airways	231.20	3463.71		3694.91
Swiss Air	124.25	2255.87		2380.12
KLM Royal Dutch	160.68	1699.14		1859.82
Gulf Airways	52.96	141.75		194.71
Alitalia		855.54		855.54
Korean Air		195.84		195.84
Uzbekistan Airways		147.91		147.91
Air Mauritius		200.67		200.67
Kenya Airways		126.17	117.17	243.34
Delta Airlines		48.33	949.42	997.75
Egypt Air		92.32		92.32
All Nippon Airlines		116.83		116.83
Air Canada		224.79		224.79
Emirates		111.67		111.67
Martin Air		0.62		0.62
Japan Airlines		50.32		50.32
Asiana Airlines		15.87		15.87
Bellview Airlines		12.40		12.40
				0.00
				0.00
TOTAL:	11121.48	10027.96	1099.34	22248.78

सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन

***528. श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के बीच चल रहे विवादों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विवादों का ब्यौरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मणिपुर राज्य में सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देने हेतु सरकार ने कोई विशेष प्रावधान किया है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और राज्य के कितने जिलों को इसके अन्तर्गत शामिल किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान राज्य सरकारों के बीच अंतर विभागीय विवादों में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ङ) मणिपुर राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र को उसके जल संसाधनों के विकास के लिए उचित प्राथमिकता दी जाती है।

(च) परियोजना कार्यों को शीघ्र करने के लिए वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए॰आई॰बी॰पी॰) के तहत निम्नलिखित दो परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी॰एल॰ए॰) दी गई है:

परियोजना	लाभान्वित जिले	वर्ष 1996-97 के दौरान जारी केन्द्रीय ऋण सहायता	वर्ष 1997-98 के दौरान जारी केन्द्रीय ऋण सहायता (करोड़ रुपये में)
खुग	चुराचांदपुर	4.3	6.0
थौबल	इम्फाल उखरूल सेनापति, थौबल	शून्य	20.0

Withdrawal/Modification of DOP & T Memoranda Regarding SC/ST Employees

*529. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether certain Office Memoranda were issued by the Department of Personnel and Training on 30th January, 2nd July, 22nd July, 13th August and 29th August, 1997 containing the directions which have adversely affected the recruitment and promotional career of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees;

(b) whether the All-India Confederation of SC/ST Organisations had made representations to the Prime Minister and the Home Minister for withdrawal/modification of the above office memoranda; and

(c) if so, what action Government have taken/or propose to take on the above representations for withdrawing/modifying the said office memoranda?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) All these Office Memoranda, except the Office Memorandum dated the 13th August, 1997, on different aspects of the reservation policy, have been issued in implementation of various judgements of the Supreme Court. The Office Memorandum dated August 13, 1997, issued in pursuance of Article 16 (4A) of the Constitution, continues reservation in promotions which, otherwise, would have ceased after November 15, 1997.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise, in view of (a) above.

किसानों को घटिया किस्म के बीजों का वितरण

*530 **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में किसानों को नकली और घटिया किस्म के बीज वितरण की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 में राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ग) वर्ष 1998 में खरीफ और रबी की फसल हेतु राजस्थान के लिए उन्नत किस्म के बीजों के वितरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने मिलावटी तथा घटिया किस्म के बीजों की शिकायतें प्राप्त होने की सूचना दी है। दर्ज किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा विवरण-I में है। (नीचे देखिए)

(ग) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।